

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2297

जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

फेम इंडिया के अंतर्गत पारंपरिक बैटरी वाहनों को दी जाने वाली रियायतों की स्थिति

2297. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच कि सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) एंड इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (फेम) योजना के अंतर्गत पारंपरिक बैटरी वाहनों को रियायतें देना बंद कर दिया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने वाली फेम भारतीय योजना के पहले चरण को अगले छह माह बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दिया है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) और (ख): जी, हां। (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) योजना के तहत पारम्परिक बैटरी वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहनों के लाभ दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से समाप्त कर दिए गए। योजना की अधिसूचना में इस योजना के चरण-I में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर उपर्युक्त रूप से इसकी समीक्षा का प्रावधान है।

(ग) और (घ): जी, हां। भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 2 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना नामतः फेम-इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] (चरण-I) तैयार की। योजना के चरण-I को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बढ़ोतरी दिनांक 31 मार्च, 2019 तक थी।
